†प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: तो डिबेट का ऐलान कीजिए।

†[پروفیسر سیف الدین سوز: تو ڈبیٹ کا اعلان کیجئے۔]

श्री सभापति: आपसे बात करने के बाद कर दूंगा।

Naxalites killed in different States

*203. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of naxalites killed in different States during the last three years, State-wise and year-wise; and

(b) the steps taken by Government to fight this naxalite problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Details of naxalites killed in different States in the last three years are as under:

Name of States	2002	2003	2004	2005 (as on 28.2.2005)
Andhra Pradesh	87	163	47	30
Jharkhand	13	21	18	3
Chhattisgarh	10	8	14	-
Bihar	22	9	1	-
Maharashtra	-	9	2	-
Orissa	1	1	-	2
Uttar Pradesh	6	3	-	1
Madhya Pradesh	-	-	1	-
West Bengal	1	-	1	-
Karnataka	-	2	-	2
Tamil Nadu	1	-	-	-
TOTAL:	141	216	84	38

†[ ] Transliteration of Urdu Script.

(b) Keeping in view that the naxal problem is not merely a law and order problem, the Central Government has adopted a multi-pronged counter strategy which takes into account the security as well as developmental aspects of the problem.

The Government has asked the naxal affected States to intensify anti-naxalite operations keeping the door for a peace dialogue with naxal groups always open. Besides reviewing and co-ordinating the steps taken by the States to counter the menace of naxalism by the Coordination Centre and the Task Force on Naxalism, the MHA provides financial Assistance to the naxal affected States in the form of reimbursement of the security related expenditure under the Security Related Expenditure (SRE) scheme. Funds are also provided for modernization of State Police forces for upgrading the weaponry, equipment mobility, training etc. under the Police Modernization (PM) Scheme to enable them to effectively meet the threat to internal security and law and order posed by the naxals.

On the development side, the Central Government has advised the States to accord a higher priority in their annual plans for the accelerated integrated development of the naxal affected districts. On its part, the Central Government has included 55 districts in 9 States badly affected by naxalism under the Bacward Districts Initiative (BDI) component of the Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY).

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, यह स्वागत की बात है कि नक्सल समस्या के लिए केन्द्र सरकार ने सुरक्षा में कड़ाई, विकास में तेजी और शांति वार्ता के खुले दरवाजें—यह बहुआयामी नीति अपनाई है। लेकिन इससे एक समस्या यह खड़ी हुई है कि इन तीन नीतियों में हर प्रदेश अपने हिसाब से नीति अपनाता है। एक प्रदेश कड़ाई करता है, दूसरा बातचीत शुरु करता है और तीसरा वहां विकास के काम शुरू करता है। इसके कारण नक्सलवादी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। इसे देखते हुए क्या केन्द्र सरकार इसकी एक राष्ट्रीय नीति अपनाएगी, जो सुरक्षा की कड़ाई, बातचीत और विकास में सभी प्रान्तों में सर्व रूप से एक होगी और क्या इसके लिए गृह सचिवों की कोई एक कायम-स्वरूपी समिति बनाई जाएगी, जो इसे देखे, ताकि नक्सलवादी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर नहीं भागें?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, इस मामले में गृह मंत्री और प्रान्तों के गृह मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की भी बैठक हुई है और इसमें इसके बारे में गहराई में जाकर चर्चा हुई। गृह सचिव के स्तर पर भी एक कमेटी काम कर रही है, जिसमें प्रान्त के गृह सचिव और प्रान्त के चीफ सेक्रेटरी और डीआइजी भी हिस्सा लेते हैं और वे नीति बनाते हैं कि दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए किस प्रकार से इसके ऊपर अमल किया जाएगा या आगे चल कर भी किया जाएगा, इसे करते हैं।

एक दूसरी कमेटी है, जो हमारे केन्द्र के स्पेशल सेक्रेटरी, जो सिक्यूरिटी के मामले देखते हैं, उनके तहत भी काम करती है और वे दो महीने में, तीन महीने में बैठ कर इस पर चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर हमारी जो नीति है, वह इस प्रकार है कि नक्सलिज्म नहीं फैले, इसलिए सरकार को कार्रवाई करनी है और मजबूती से कार्रवाई करनी है। मगर इसके साथ-साथ इसमें कोई आर्थिक प्रश्न का निर्माण हो रहा है और इसकी वजह से तक्सलिज्म बढ़ रहा है, यह सामाजिक हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है, तो इसे भी ध्यान में रखें और इस पर भी काम करें। स्टेट्स को यह बताया गया है कि जितना पैसा चाहिए, जितना फोर्स चाहिए या दूसरे इक्विपमेंट्स चाहिए, वे आपको देंगे और जब भी कार्रवाई करते हैं और प्लान बनाते हैं तो बाजू के जो स्टेट्स हैं, उनसे प्रेम के साथ चर्चा करके यह करना है। इस प्रकार सब मिलकर यह करना है।

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, वर्तमान में यह लगता है कि नक्सलवादियों का सबसे बड़ा लक्ष्य बड़े-बड़े राजनेता बने हैं। आज आंध्र प्रदेश में सोनिया गांधी जी की रैली है और वहां उनके बहिष्कार की घोषणा की गयी है, वेंकैया नायडू जी का हैलीकॉप्टर बिहार में जलाया गया और चन्द्रबाबू नायडू पर भी इसी प्रकार का हमला हुआ था। इस तरह विभिन्न प्रांतों में राजनेताओं को लक्ष्य बनाया जा रहा है और किसी एक राजनीतिक दल के नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को लक्ष्य बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए क्या केन्द्र सरकार इस पर कोई विशेष नीति अपनाएगी ताकि इन राजनेताओं की सुरक्षा, विशेषकार इन 9 प्रांतों में हो?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। उसी प्रकार का प्रयास नक्सलवादियों की तरफ से किया जा रहा है। पहले वे चाकू, कुल्हाड़ी और तलवार से काम करते थे। बाद में pistol और रायफल्स से काम करने लगे, फिर ए॰के॰ 47 पर आए और आज वे ग्रेनेड और माइंस पर पहुंच गए हैं और ज्यादा परिमाण में भय फैलाने के लिए नेताओं पर व पुलिस फोर्स के लोगों पर जजंबा किया जा रहा है। महोदय, इस बारे में हमारी नीति को हम कड़े तरीके से लागू करेंगे। उस बारे में जो करना है, उस पर भी हम सोच रहे हैं और ज्यादा सोचकर यह जे भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण लगाया जा सकता है, हम इसे देखेंगे व हम सब लोग आपके साथ भी चर्चा करके नीति बनाएंगे।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने नक्सली ग्रुपों के साथ शांति वार्ता का दरवाजा खोल दिया है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन 9 राज्यों की सरकारों ने, वहां के गृह मंत्रियों ने अब तक कितनी बार इस प्रकार की बैठकें बुलायी हैं? दूसरे आपने कहा कि नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की व्यवस्था की जाएगी। तीसरे आपने कहा कि 9 राज्यों के 55 जिलों को राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अधीन शामिल किया गया है। तो प्रश्न यह है कि आपने नीति बहुत अच्छी बनायी है, लेकिन इनके क्रियान्वयन की दिशा में राज्य सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं और क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि अब तक राज्य सरकारों को आपने इन हथियारों से नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए कितनी धनराशि दी है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, इस नीति के अलग-अलग पक्षों से जुड़े सारे लोगों ने बैठकर यह नीति बनायी है और उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। इसका जिक्र उनके manifesto और दूसरे कागजातों में भी नजर आता है। खासकर आंध्र प्रदेश में बातचीत का सवाल बड़े पैमाने पर उठाया गया था। वहां मुख्य मंत्री, गृह मंत्री और दूसरे एकैडेमिसियंस की मदद से चर्चा हुई और उस बारे में 3-4 दफा उनकी मीटिंग्स और चर्चा हुई है। महोदय, वहां पर मुख्य सवाल यह पैदा हुआ है कि नक्सली नेता या उनके सहयोगी हथियार लेकर घूमेंगे या नहीं? उस बारे में सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बारे में थोड़ासा अंतर नजर आता है, लेकिन बाकी दूसरी चीजों पर कोई अंतर नजर नहीं आता है। जहां तक पैसे का सवाल है, पैसा बहुत दे रहे हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, हथियार के लिए पैसा दे रहे हैं, इंटैलीजेंस को मजबूत बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा दे रहे हैं और कम्युनिकेसन के लिए पैसा दे रहे हैं। उसके अलावा उन्हें यहां से जो हम paramilitary forces देते हैं और उसके लिए जो पैसा चार्ज करते थे, वह भी बंद कर दिया है। हम एक बटालियन के लिए 13 करोड़ रुपया चार्ज करते थे, वह भी बंद कर दिया है। महोदय, इस प्रकार से हजारों करोड़ की संख्या में पैसा अलग-अलग प्रांतों को दिया जा रहा है और नक्सल affected areas में उनको वहां पर 23 बटालियंस 3 साल तक रखने की इजाजत दी गयी है। इस प्रकार से एक ओर आर्थिक परिस्थिति में सुधार करके, सामाजिक परिस्थिति में सुधार करके, दूसरी ओर पुलिस और armed forces की शक्ति बढ़ाकर और तीसरी तरफ सभी लोगों में तालमेल या coordination पैदा करके इस समस्या को handle करने का प्रयास किया जा रहा है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, one basic issue has to be understood by one and all. I would like to know from the hon. Minister how the Government of India is viewing this problem, because, time and again, people say it is happening because of socio-economic considerations. The real point is, who are these naxalites or the extremists? They are a part of the Communist Movement, who believed that people were not following the revolutionary line, as they were expected to. Hence, they formed a separate group and took to arms. That is the issue. The Communist parties are working for the people. The Congress and BJP may also be working for the people. But these people are saying that power would come through the barrel of the gun.

Sir, through you, my request to the hon. Home Ministry is, let us understand the basic theme of the naxalites. They want to capture power through the barrel of the gun. Everybody talks about socio-economic problems, that we need to understand their problems, and so on. But, what is the approach of the Government? ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: What is your question? ...(*Interruptions*)..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That is my question. What is your problem? ...(*Interruptions*)... It is a basic question ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this is not fair ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: नहीं -नहीं क्वेश्चन हो गया। ...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is not the way, Sir. I am withdrawing my question ...(*Interuptions*)... I am withdrawing my question.

श्री सभापति: ठीक है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this is not the way. Is this the way, to disturb? They don't want to even hear the question ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आपने क्वैश्चन बता तो दिया!...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we are the victims. These people simply sit like and then go away...*(interruptions)*...

श्री सभापति: आपकी तरफ से वे वहीं बोलना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री एम॰ वेंकैया नायडु: वे क्या बोलना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: नहीं, आप गुस्सा मत करिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, he is an affected person. He should be allowed to complete what he has to say.

श्री सभापति: उन्होंने उठा तो दिया ना। ...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am raising a fundamental issue ..*(interruptions)*.. I am a Member of this House and for six years now, I have heard the lectures. My question is — is the Government of India viewing it as a challenge to the system? If so, is the Government of India going to take the States into confidence? It is not correct to simply view it as a law and order problem. It is a security-related problem. Will the Government of India guide the States and take a firm political stand against the movement and then, provide the necessary support?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I agree with the hon. Member that those who are involved in naxalite activities say that justice will not be done through the democratic system. They say that it has to be done by using force, through the gun and through violence, if that is necessary. There is

a basic difference between the two approaches. Because of that, the Communist paty believes that the system that we have adopted can also deliver and it is not always necessary to use the gun. But, the naxalites and those who speak the language of the Mao philosophy and all those things, say that — others may not accept that point — it has to be done through the gun and violence. This is the basic difference. We have studied this issue very carefully. They are people who are not having confidence in the system which we have adopted here and they are trying to adopt a different system which is violent, which is terrorist. But then, there ar others also who are economically affected, and without understanding the ideological nuances, they have joined them. There are also others who do not understand anything. The flow is on; they have joined the flow and are carried away by the flow. So, this problem has to be examined very carefully, and after examining carefully, the different sections have to be dealt with in different manners. We are trying to persuade them saying that violence and force will not work in the country because 90 per cent of the people in India believe in this system and believe in peaceful uprise. They do not believe in violence. They do not believe in using force. Even out of the remaining ten per cent, there are people who do not believe only in these things; only a few people believe in this. So, we are trying to convince them and persuade them to accept this approach, through dialogue. And then, if there are grievances we are trying to remove those grievances. Ultimately, if this does not work, the Union Government as well as the State Governments have a duty to perform and they shall perform their duties. For this, we are having discussions at all levels. Fortunately for us, there are lots of areas on which there is full agreement. There are some areas where there are some differences of opinion. Those differences of opinion could also be removed.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am a little surprised at this reference to the PWG and some of the left-wing extremists as being part of the Communist Movement. This naxalite movement arose some forty years back and I think you don't find this movement anymore. So, I think it has more to deal with specifics of the socio-economic conditions. The hon. Home Minister has spoken about many other things...*(interruptions)*...

श्री सभापति: बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।

SHRI NILOTPAL BASU: So far as the land question is concerned, how is it being sought to be addressed by the Government of India in consultation with State Governments? I think that is the key question because they

have nothing to do with the Communist movement, but with the extreme inequity that exists in terms of land and agrarian relationship, that is being exploited by these groups to spread violence. So, please tell the House as to how the Government of India tries to address the land question in these areas.

श्री सभापति: माननीय गृह मंत्री जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर सभी मैम्बर्स जानकारी करना चाहते हैं। अगर आप इस बारे में जितने भी नक्सलवाद एफेक्टेड स्टेट्स हैं, उनके एम.पीज. से, पार्टियों के लीडर्स से बैठकर बात कर लें तो उससे एक दूसरे को समझने में और समझने के बाद क्या कार्रवाई की जाए, इस पर एकमत हो जाएंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री अश्विनी कुमार: सर, हाऊस में चर्चा करा लीजिए।

श्री सभापति: हाऊस में?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, your direction is acceptable to us. We will organise the meeting and if the matter is discussed on the floor of the House, it is welcome, or, any other thing, which you think is fit, is welcome.

श्री सभापति: पहले आप चर्चा कर लीजिए, फिर जरूरत पड़ेगी और यदि हाऊस के फ्लोर पर डिसकस करना होगा, Then we will think about it.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The only thing is, when we discuss it in a Committee, it is not an open House; when we discuss it in the House, it is an open House. So, discussing it on the floor of the House, or, whatever is your direction, is acceptable to us.

श्री सभापति: अगर आप ज्यादा उचित समझतें हों, तो हाऊस के फ्लोर पर डिसकश कर लेंगे और यदि आप अलग करना चाहें, तो अलग कर लीजिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल: सर, जैसा आप आदेश करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री दत्ता मेघे: सर, आप हाऊस में करा लीजिए। आप चाहें तो पहले मीटिंग बुला लीजिए।

श्री सभापति: हां, मीटिंग बुला लूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री दत्ता मेघे: हाऊस में ही डिसकस होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: ठीक है, सदन में हो जाएगा।

श्री शिवराज वी. पाटिल: सर, सदन में डिसकस करने से अच्छा होगा।

श्री सभापति: चलिए, सदन में कर लेंगे। नैक्स्ट क्वेश्चन। ...**(व्यवधान)**...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: It involves many issues. ...*(interruptions)*

श्री सभापति: अब सदन में चर्चा होगी, इसको आप छोड़िए।

श्री शिवराज वी. पाटिल: सर, इस प्रश्न का तो जवाब दे दूं, जो बसु जी ने उठाया था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, पहले बसु जी के क्वैश्चन का जवाब हो जाए। ...(व्यवधान)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I will reply to this quesion with your permissicn. The issue raised by the hon. Member is really very pertinent. Wherever the land reforms have taken place in a proper manner, this problem is not only much visible there. The second issue is unemployment. ...*(Interruptions)*..

श्री सभापति: आप बैठिए। मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... चलिए, इसके ऊपर हाऊस में चर्चा की जाएगी। यह चर्चा किस समय की जाएगी, वह बिजनेस एडवायजरी कमेटी में बैठकर मैं तय कर लूंगा। नैक्स्ट क्वैश्चन, 204-श्रीमती हेमा मालिनी।

Rejection of foreign assistance

†*204. SHRIMATI HEMA MALINI:††
SHRI B.K. HARIPRASAD:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) the steps taken to ensure that the millions of dollars pouring into India goes to the legitimate desination, the Tsunami victims, and not to the unscrupulous who have managed to divert some or most of them for themselves;

(b) whether it is a fact that Government have declined the offer for aids from US and other foreign Governments and overseas agencies; and

(c) if so, what are the reasons for such rejection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. REGUPATHY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†Questions No. 204, 211 and 212 were taken together.
†† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Hema Malini.